कहां गये वे झाड़ू हाथ में लेकर फ़ोटो खिंचवाने वाले ? आज शहर को जरूरत है उनकी

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्वच्छता अभियान के नाम पर नौटंकी करने वाले आज कहां छिपे बैठे हैं ? वैसे तो इस स्मार्ट शहर में कभी सफ़ाई देखी नहीं गयी, हमेशा कहीं न कहीं गंदगी के ढेर सड़ते देखे गये हैं। परंतु बीते एक सप्ताह से गंदगी के इन बड़े होते ढेरों ने नागरिकों का ध्यान अपनी ओर खासा आकृष्ट किया है।

करीब 3 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर चंडीगढ से बाकायदा रेल में बैठ कर इस शहर की एक झुग्गी बस्ती में सफ़ाई का नाटक करने आये थे। एक सुंदर सा झाड़ू हाथ में लेकर जब वे सफ़ाई करने का अभिनय करने लगे थे तो धड़ाधड़ फ़ोटो खिंचने लगे। चापलूस भी कौन सा मौका चूकने वाले थे उन्होंने भी अपने नम्बर बनाने के लिये पूरा नाटक खेला। सारे मीडिया में इस नाटक की झलकियां प्रकाशित हुई। सभी **'कलाकार'** फूले नहीं समा रहे थे। इसी तर्ज पर स्कूलों में मास्टर और अस्पतालों में डॉक्टर अपना-अपना असली काम छोड़ कर सफ़ाई के नाटक को खेलने में जुट गये।

लेकिन नाटक, नाटक होता है और काम काम होता है। नाटक खेलने से काम पूरा नहीं होता। काम तो करने से ही पूरा होता है तथा वही कर सकता है जो उसके योग्य होता है, दिखावटी लोग तो केवल काम को बिगाड़ सकते हैं।

सफ़ाई करने के योग्य लोगों को इस सरकार ने गत दसियों दिन से हड़ताल पर बैठा रखा है। सर्वविदित है कि न तो शहर की जरूरत के मुताबिक उनकी संख्या पर्याप्त है और न ही महंगाई के इस जमाने में पेट भरने लायक वेतन ही मिलता है। पहले जब भी ये लोग हड़ताल पर जाते थे तो स्थानीय अधिकारी झूठे आश्वासन देकर इन्हें काम पर लगा लेते थे परन्तु इस बार इन्होंने आर-पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया है। लेकिन सीधे मुख्यमंत्री से वार्ता के बावजूद नतीजा वही ढाक के तीन पात।

समस्या का सही समाधान करने की अपेक्षा सरकार एक से बढ कर एक षड़यन्त्रकारी योजनायें बनाती है। ऐसी ही एक योजना है ठेकेदारी। सफ़ाई का ठेका किसी ठेकेदार को दे दिया जाता है। लेकिन ठेकेदार को पेमेंट तब मिलती है जब वह अफ़सरों को मोटा कमीशन दे और जब तक उसे नगर निगम से पेमेंट नहीं मिलती वह अपने सफ़ाईकर्मियों को वेतन नहीं दे सकता। ऐसे में महीनों तक कर्मी वेतन अटका रहता है।

अब, जब पूरा शहर गंदगी से बजबजा रहा है तो भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं क्योंकि सरकार को तो यहां रहना नहीं, वह तो विदेशी दौरे में या फ़िर शाही दौरे में रहती है।

रेलवे लाइन पार करने के खतरे तो बताते हैं लेकिन उपाय नहीं करते

फ़रीदाबाद (म.मो.) रेलवे लाइन पार करने से दिन ब दिन बढ़ती दुर्घटनाओं से रेल विभाग की सेहत पर तो कतई कोई असर नहीं, हां पुलिस की मुसीबत जरूरत बढ जाती है। अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पाने या इसे कम से कम करने के लिये पुलिस आये दिन किसी न किसी स्टेशन पर लठ लेकर यात्रियों को ट्रैक पार करने से रोकती है। लेकिन जब सैंकड़ो की संख्या में यात्री एक साथ ट्रैक पार कर रहे हों तो 5-10 पुलिस वालों की कुछ नहीं चल पाती।

दरअसल यह सब रेलवे की हरामखोरी की वजह से है। यदि रेलवे वास्तव में ही चाहे कि लोग ट्रैक पार न करें तो कोई पार कर ही नहीं सकता। इसके लिये सिर्फ़ दो काम जरूरी हैं। एक तो पर्याप्त मात्रा में एस्कलेटर (स्वचालित सीढियों वाले) पुल होंऔर दूसरा ट्रैक से ट्रैक के बीच ऊंची ग्रिल लगाई जाये। इस तरह की ग्रिल पहले लगभग हर बड़े स्टेशन पर हुआ करती थी। धीरे-धीरे वे ग्रिलें टूटती व उखड़ती चली गयी। न तो किसी ने उनकी मुरम्मत करने की जरूरत समझी न ही नई लगाई। बस टूटी ग्रिलों का कबाड़ा बेच खाया।

जुमलेबाज़ों की सरकार तो उक्त दोनों काम करने वाली है नहीं, इसके लिये यात्रियों व अन्य नागरिकों को सुसंगठित होकर संघर्ष चलाना पड़ेगा। क्योंकि बिना लड़े कुछ मिलता नहीं और यह सरकार तो आन्दोलन की भाषा के अलावा और कोई भाषा समझती ही नहीं।

थाना एनआईटी क्षेत्र में शराब व जुआ माफ़िया सक्रिय

फ़रीदाबाद (म.मो.) थाना एनआईटी पुलिस की मिली भगत के चलते एनआईटी क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से गोरखधंधा करने वालों के धंधे जमकर चल रहे हैं। थाना एनआईटी से चंद कदमों की दूरी पर 5-सी ब्लॉक में रोज़ाना लाखों रुपये का जुआ खुलेआम चल रहा है। दाना मैच की बुक भी लगाई जा रही है।

5-सी ब्लॉक के इसी घर में कई वर्षों से अवैध शराब का धंधा भी जम कर हो रहा है। थाना एनआईटी में इस शराब माफ़िया की सैटिंग (दलाली) का काम बड़खल विधायक सीमा त्रिखा के तथाकथित चाचा शराब माफ़िया तदेन्द्र टंडन ने थाना एनआईटी में वर्षों से तैनात सब इंस्पेक्टर व एक ए एस आई जो टंडन के विश्वसनीय हैं, इन्हीं दो काली भेड़ों द्वारा करवाया हुआ है। टंडन को इन दो काली भेड़ों के साथ अक्सर शाम ढलते ही कर्मकांड करते 5 नम्बर में अक्सर देखा जा सकता है।

कहने को एक तरफ़ पुलिस कमिश्नर शहर में स्वच्छ एवं भय मुक्त माहौल देने के लिये सभी थाना चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर थाना एनआईटी पुलिस आदेशों को ठेंगा दिखाकर माफ़िया टंडन के आदेशों की पालना कर शहर में जुआ, सट्टा व अवैध शराब बिकवाते नज़र आ रही है। यह काम कोई चोरी-छिपे नहीं बल्कि दिन दहाड़े बीच मार्किट में बसे सी ब्लॉक में हो रहा है।

एनएच 5 में करीब आधा दर्जन अवैध शराब तस्करों व ऑनलाइन कैसिनो संचालकों से मंथली इकट्ठी कर थाने में पहुंचाने का काम भी टंडन का काफ़ी समय से चल रहा है। सूत्रों के अनुसार अगर कोई धंधेबाज़ टंडन को पुलिस के नाम पर मंथली देने से मना करता है या फ़िर वो धंधेबाज़ खुद थाना एनआईटी में सैटिंग करने को बात करता है तो टंडन थाना एनआईटी में तैनात इन्हीं दो काली भेड़ों को भेज उसका धंधा बंद कर देता है।

यहां पाठकों को यह बता दें कि कभी पुलिस कमिश्नर सुभाष यादव के समय इस टंडन की ऐसी चूड़ी टाइट की गई थी कि टंडन यादव के रहने तक बिल में घुसा रहा था।

जियो-मरो, पुलिस और प्रशासन की बला से

भद्दी इंजीनियरिंग और घटिया गुणवत्ता का नमूना बना राजमार्ग का बाटा मोड़ फ्लाईओवर

विवेक की विशेष रिपोर्ट

शोलापुर महाराष्ट्र में मोटरसाइकिल से जा रहे मां बेटे की सवारी गड्ढे में गिर गई जिससे महिला की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने मामले में लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने का जिम्मेवार बता मां की मौत का ठीकरा बेटे के सिर फ़ोड़ दिया। इंजीनियरिंग, रखरखाव, गुणवत्ता जैसे पहलू नज़रअंदाज कर दिये गये।

सड़क इंजीनियरिंग के एक से एक घटिया नमूनों से भरे भारत देश में स्मार्ट सिटी फ़रीदाबाद का मथुरा रोड पर नया बना बाटा चौक फ्लाईओवर भी अपना विशेष स्थान रखता है। खुदी हुई सड़कों, बेतहाशा अतिक्रमण और निम्न गुणवत्ता का एक बेहया प्रशासनिक नमूना।

फ़रीदाबाद निवासियों के लिये बाटा मोड़ फ्लाईओवर का बेतरतीब जाम कोई नई बात नहीं है। परन्तु विडम्बना ही है कि इतनी चौड़ी सड़क पर भी इस कदर जाम लगते हैं। ट्रैफिक का सारा दारोमदार भगवान भरोसे ही छोड़ रखा है।

समस्या प्रारम्भ होती है सड़क इंजीनियरिंग की खामियों से, जिसमें दोनों तरफ़ पचास प्रतिशत हिस्से पर कोई पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया। मैट्रो के कार्य की दुहाई देकर पल्ला झाड़ने की कवायदें बराबर चल रही हैं, जबकि मैट्रो को पूर्ण रूप से संचालित हुये अरसा हो गया। ध्यान रहे कि राजमार्ग का यह हिस्सा न सिर्फ़ रेल लाइन के दोनो ओर बसे शहर को परस्पर जोड़ता है बल्कि बल्लबगढ को भी शेष महानगर से।

प्रशासनिक हब सेक्टर 12 से निकलकर ज्यो ही राजमार्ग पर आते हैं तो निर्मित सड़क का 30 प्रतिशत दाहिना खुदा हुआ हिस्सा तीन फीट की गहराई एवं लगभग 40 गुणा 6 मीटर की लम्बाई चौड़ाई के साथ पिछले कई महीनों से न जाने किसकी राह देख रहा है। शायद अहिल्या को किसी राम के हाथों उद्धार की प्रतीक्षा है।

वहीं बायां भाग जो कच्ची सड़क के रूप में कुल सड़क का लगभग 50 प्रतिशत है, जर्जर अवस्था में पड़ा है। इस जर्जर मार्ग पर मानक मोटर्स एवं राजपूत मोटर्स की बिकाऊ गाड़ियों की लाइन अलबत्ता मिल जायेगी। यानी लोग तो फ़से रहे जाम में और गाड़ियों के शोरूम की मुफ़्त पार्किंग चलती रहे।

बाटा चौक से हार्डवेयर चौक की ओर मुड़ते ही 12 गुणा 7 फ़ीट का एक बोर्ड सड़क के बीचो बीच 45 डिग्री के कोण पर कई महीनों से टूटा पड़ा है। इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। ट्रैफ़िक में रुकावट पर किसी को खेद नहीं और दुर्घटना हो जाये तो नई बात क्या है!

हार्डवेयर चौक से हाईवे को जोड़ने वाले रेल पुल पर चढेंगे तो गड्ढों में खोई सड़क और बेतरतीब खड़े ऑटो-रिक्शों की भीड़ आपको चुनौती पेश करेगी। इस कारण पीछे तक का सारा ट्रैफ़िक प्रभावित होता रहता है।

बाटा चौक फ्लाई ओवर को जोड़ों की रिपेयरिंग के नाम पर महीनों बंद रखा गया। परन्तु जनता के इतने त्याग के बावजूद गैप को ठीक से भरा न जा सका। आप कितनी ही लग्जरी कार से क्यों न जायें परन्तु गैप अपने वहां होने का धक्का सबूत आप को दे ही देंगे।

हार्डवेयर की तरफ़ पुल पार करते ही एक अन्य बोर्ड टूट कर महीनों से सड़क पर पड़ा है। जिससे बचकर या उस पर चढ़कर जाने को राहगीर मजबूर हैं ताकि खतरे से खेलने की कसर न रह जाय!

शहर से हाइवे पर जाने या हाइवे से शहर में जाने जैसी दोनों ही सूरतों में यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर ही आते-जाते हैं। हाइवे से निकासी एवं प्रवेश स्थानों

पर गड्ढों की भरमार है। ऐसे में चालक या तो गड्ढों से बचें या हाइवे पर आते-जाते तेज रफ़्तार अन्य वाहनों से।

इनके बीच ट्रैफ़िक पुलिस का थकेला सा सिपाही पूरी कोशिश करता है, ट्रैफिक को ज्यादा घटिया तरीके से संचालित करने की जिसमें लोगों की जल्दबाजी के साथ-साथ सड़कें स्वयं भी अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं।

पूछा जा सकता है कि चौड़ी सड़कें बनाने का क्या लाभ जब घटिया इंजीनियरिंग से सारी जगह को बर्बाद ही करना है। सरकारी पैसा, समय व्यक्तिगत स्तर पर उठाई गई आम जन की परेशानियों एवं सहनशीलता का कोई मोल नहीं जब अंत में भी वैसा ही नज़ारा है जैसा प्रारम्भ में था।

फेसबुक एवं ट्विटर पर मदद पहुंचाने और समस्या का समाधान का दावा करने वाली डिजिटल सरकारों के हाइटेक विधायकों, मन्त्रियों को आम जन के मतलब वाली आधारभूत संरचना प्रदान करने में कोई दिलचस्पी प्रतीत नहीं होती। न केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर और न राज्य सरकार के मंत्री विपुल गोयल की प्रेस विज्ञप्ति में भी यह चर्चा मिलेगी।

रंगहीन डिवाइडर, बोर्ड रहित मार्ग, गड्ढों में खोई सड़कों के चलते यदि दुर्घटनायें होती हैं तो उसका जिम्मेवार सीधे-सीधे शासन-प्रशासन हुये। जो इन स्कीमों में पैसे भी चट कर जाते हैं एवं आधे अधूरे प्रोजेक्टों को गड्ढों समेत छोड़ देते हैं, आम नागरिक की कब्रगाह बनने के लिये।

विरोधाभासी सड़क व्यवस्था का चरित्र भी वैसा ही दोहरा है जैसा कानून व्यवस्था का। पुलिस, गड्ढे खुले छोड़ने वालों को छोड़ कर गड्ढे में गिरने वाले व्यक्ति को ही मां का हत्यारा साबित करने पर तुली होती है। वाह रे स्मार्ट सिटी!

अतिक्रमण का अतिक्रमण

अतिक्रमण हटाने का ड्रामा दिल्ली से फ़रीदाबाद हर रोज़ जारी है। ऐसे में यह देखना भी प्रासंगिक है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसको हटाया जा रहा है?

मथुरा हाईवे से सेक्टर 12 की ओर मुड़ते ही सिटी ढाबा, धरमा ढाबा एवं ढाबा जंक्शन नामक 3 ढाबों के दर्शन होते हैं। इन ढाबों पर खड़ी होने वाली गाड़ियॉ सारी सड़क को जहां एक ओर जाम करती है वहीं आमजन को सड़क दुर्घटना के मुंह में भी धकेलती हैं।

इन ढाबा मालिकों को अतिक्रमण से रोकने वाला कोई नहीं। जबकि मात्र 100 मीटर की ही दूरी पर सचिवालय, न्यायालय जैसे प्रशासनिक व न्यायिक संस्थान मौजूद हैं। जाहिर है इन्हें संरक्षण मुफ़्त में नहीं मिल रहा।

यही नज़रअंदाजी दर्शाती है कि क्यों इन पर इतनी मेहरबानी बरसाई जा रही है। थोड़ा और आगे आने पर शनि मंदिर के दर्शनों को आए भक्तों की गाड़ियां सड़क घेरे खड़ी मिलेंगी। शनिवार को रात इन बिना स्ट्रीट लाइटों की सड़कों पर सही सलामत निकल जाना शनि में आस्था को और मजबूती देता है।

इसी प्रकार ऐन राजमार्ग पर बाटा मोड़ के एक ओर जहां मानक मोटर्स एवं राजपूत मोटर्स की गाड़ियों का कब्जा है तो दूसरी तरफ़ शराब के ठेके पर लगी गाड़ियों का।

शराब का ठेका मुख्य सड़क के ऊपर ही शायद इसलिये बनाया गया है कि यदि होश में बच निकलने का आपका प्लान है तो उस रणनीति को नशे में चलने वाले ध्वस्त कर दें।

इतना ही नहीं हार्डवेयर चौक की ओर सड़क को हर तरफ़ से बड़े-बड़े ट्रकों की पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बाटा चौक से हार्डवेयर चौक तक की सड़क ट्रकों के लिये मानों आरक्षित है। तो वहीं हाइवे के सामान्तर खाली स्थान जो कायदे से सड़क का हिस्सा है भी ट्रकों, टैम्पुओं के अतिक्रमण से पटा पड़ा है।

सड़क किनारे बने मैरिज हॉल, टाटा प्लांट एवं अन्य संस्थानों ने अपने सामने की सारी जगह पर भद्दे रूप से कब्जा जमा लिया है। यूं तो इन संस्थानों को पार्किंग सुविधा भी मिलनी चाहिये, जब विवाह समारोह इत्यादि का आयोजन होना ही है। क्या सरकार इसे एक सफल रूप नहीं दे सकती? इन मैरिज हॉल सरीखे संस्थानों के सामने का स्थान सार्वजनिक रूप से पार्किंग इस्तेमाल को दिया जा सकता है। वो भी इस शर्त पर कि इसके रख रखाव की जिम्मेदारी इन संस्थाओं पर ही होगी। ट्रकों को खड़े होने का स्थान भी चाहिये ही। तो क्या व्यवस्थित रूप में उनके लिये एक स्थान या छोटे-छोटे कई पार्किंग स्थल निर्मित नहीं किए जा सकते? विशेषकर जब जगह की कमी नहीं।

परन्तु स्मार्ट शहर के प्रशासन को इन उपायों में दिलचस्पी कम है। तो आसान है ढाबों, ठेकों, कार डीलरों से मिल-मिलकर अपनी जेवें गरम की जाये और दिखावे के लिये आंशिक रूप से दो-चार अतिक्रमण हटा दिये जाये। जनता जाये भाड़ में। निगम कमिश्नर मोहम्मद शाइन की प्रेस विज्ञप्तियां बेशक चलती रहती हैं और चलती रहेंगी।